



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2369]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2012/अग्रहायण 20, 1934

No. 2369]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2012/AGRAHAYANA 20, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2012

क्र.आ. 2870(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना (दि.मु.यो.)-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्तियाँ/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति दूरभाष, फैक्स नंबर एवं ई-मेल आई डी के अतिरिक्त अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

मुख्य योजना 2021 के अध्याय 17 विकास कोड के उप खंड 8 (2) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है। नोट के पैरा (V) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

“नये अस्थायी सिनेमाघरों को अनुमति नहीं होगी तथापि, मौजूदा अस्थायी सिनेमाघरों को नीचे दी गई शर्तों के अनुसार स्थायी आधार पर चलने की अनुमति होगी”।

i

सीटों की संख्या

—न्यूनतम 300 सीटें तथा अधिकतम 1000 सीटें जो एक अथवा अधिक हॉल में हो सकती हैं।

- | | | |
|------|---|---|
| ii | सामने की सड़क का न्यूनतम मार्गाधिकार | —18 मी. |
| iii | पार्किंग की आवश्यकता | —निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर 3 ई सी एस |
| iv | अधिकतम तल कवरेज | —50%(दि.मु.यो. 2021 के अनुसार न्यूनतम सैट बैक के पालन की शर्त के अधीन) |
| v | एफ.ए.आर. | —अधिकतम 2000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्रफल की शर्त के अधीन 100 । यदि किसी सिनेमाघर में अधिक भूमि है तो शेष क्षेत्र हरित क्षेत्र होगा । |
| vi | प्लॉट का आकार | न्यूनतम 1200 वर्ग मी. एवं अधिकतम 4000 वर्ग मी. |
| vii | अधिकतम अनुमेय ऊँचाई | —15 मी. |
| viii | स्नैक्स काउंटर इत्यादि से अलग किसी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी । | |
| ix | सिनेमाघर सिनेमाटोग्राफी एक्ट और अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हों । मल्टीप्लेक्सों को तदनुसार अनुमति होगी । | |
| x | भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, एफ ए आर प्रभार, सुधार शुल्क और अन्य प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदन अनुसार लिए जाएंगे । | |
| xi | स्थानीय निकाय और लाइसेंसिंग प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंस नवीनीकरण से पहले उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन कर लिया है । | |
| xii | सरकारी भूमि पर मौजूद अस्थायी सिनेमाघर को जारी नहीं रखा जाएगा । | |
| xiii | इस प्रकार के मामलों में यदि बड़े सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है तो उसे संबंधित स्थानीय एजेंसियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र आवश्यकता/मुख्य योजना प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहीत और विकसित किया जाएगा । | |

भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए दिल्ली मुख्य योजना 2021 में आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात् प्रत्येक मामले में उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस को उप निदेशक

कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा ।

[फा. सं. एफ 11(6)/74/एम पी/पार्ट-1]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th December, 2012

S.O. 2870(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi (MPD)-2021 under Section 11-A of the Delhi Development Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objections or suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of Thirty days from the date of this Public Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name and address. In addition to Phone Number, Fax Number and E-Mail ID.

MODIFICATION:

Following modifications are proposed in the Master Plan 2021, chapter 17 Development Code under sub clause 8 (2). Following shall be added after Para (v) of the notes:

“New Temporary cinemas shall not be permissible, however already existing Temporary Cinemas shall be allowed to continue on permanent basis as per the conditions given below”

- | | |
|--|---|
| i. Seat capacity | - Minimum 300 seats and max. 1000 seats, which may be allocated to One or More halls |
| ii. Minimum road R/W in front | - 18 mt. |
| iii. Parking requirement | - 3 ECS per 100 sqm. of Built up space. |
| iv. Maximum ground coverage | - 50 % (subject to minimum setbacks as per MPD 2021 to be adhered) |
| v. FAR | - 100 subject to a maximum built up area of 2000 sq.mt. In case a Cinema Hall has more land, the rest of the area would be kept green |
| vi. Plot Size | - Min. 1200 sq. mts & max. 4000 sqmt |
| vii. Max. Permissible Height | - 15 mts |
| viii. No commercial activity other than snacks counter etc. shall be permissible. | |
| ix. Cinema would conform to the Cinematography Act and other statutory provisions. Multiplexes shall accordingly be permissible. | |
| x. Land Use conversion charges, FAR charges, betterment levies and other charges will be levied as approved by the Government from time to time. | |
| xi. The local body and licensing Authorities shall ensure that the above conditions are complied with before renewing the license. | |

- xii. The temporary cinema existing on government land shall not continue.
- xiii. The excess land in such cases, if required, for larger public purposes shall be acquired and developed as per the local area needs/ Master Plan provisions by the concerned local agencies.

Individual cases will be processed as per the above provisions after the enabling provisions are made in the MPD 2021 for change of land use.

The text of MPD-2021 indicating the proposed modification shall be available for inspection at the office of the Dy. Director Master Plan Section, 6th Floor Vikas Minar, IP Estate New Delhi – 110002 on all working days within the period referred above.

[F. No. F. 11(6)/74/MP/Pt.-1]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.